>

Title: Need to permit the export of Non Basmati rice.

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): महोदय, देश में चावल के निर्यात के बारे में बोलने जा रहा हूं। मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है। हम भारत देश में अनेक देशों से कृषि उपज लेते हैं। सौभाग्य से पिछले वर्ष हमारे देश में कपास, गेहूं, चावल की फसल अच्छी हुई। इसके चलते किसानों ने मांग की थी कि कपास, चावल के निर्यात के लिए सरकार अनुमति दे। पिछले महीने सरकार ने गेहूं, कपास के लिए अनुमति दी है, लेकिन चावल पर संख्यात्मक निर्बंध लगाते हुए अनुमति दी गई है। चावल की देश में बहुत उपज हुई है। यदि चावल का दूसरे देशों में निर्यात होता, तो देश में किसानों को चावल का अधिक मूल्य मिल सकता था। जैसे कि कपास का अधिक मूल्य मिल रहा था, जब हम निर्यात कर रहे थे। अनेक कृषि संगठनों ने मांग की थी कि कपास के निर्यात पर बंदिश हटाई जाए और निर्यात होने दीजिए। जब कपास की मांग थी, तब सरकार ने अनुमति नहीं दी। जब विश्व के बाजार में मंदी आए, तब सरकार ने अनुमति दी है, जिसके कारण किसानों का भारी नुकसान हुआ है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार की गलत नीतियों के कारण किसानों का नुकसान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि देश में अनाज का बड़ी संख्या में भण्डारण है और देश में अनाज सड़ रहा है।

सभापति महोदय : हंसराज जी, यदि एक्सपोर्ट करने से भारत में नॉन-बासमती की चावल की किल्लत हो गई, तो क्या होगा?

श्री हंसराज गं. अहीर : नहीं होगी, वही मैं आपको बता रहा हूं। हमारे देश में चावल की उपज जरूरत से ज्यादा हुई है। यह सरकारी आंकड़े हैं। इसके बावजूद भी यदि हम किसानों को बलि चढ़ाते हुए देश में महंगाई को रोकते हैं तो यह गलत करते हैं। यदि हमें महंगाई रोकनी है तो नीतियों में परिवर्तन करना होगा। इसमें किसानों का नुकसान हुआ है। जिस समय साढ़े पांच हजार रुपए प्रति क्वींटल कपास बिक रहा था, उस समय सरकार ने निर्यात की अनुमति नहीं दी। लेकिन जब दुनिया में कपास की मंदी आयी, उस समय कपास के दाम देश में नहीं बढ़े। वही बात चावल के बारे में भी हो रही है। भारत के चावल की मांग अफ्रीकन और गल्फ कंट्रीज़ में है। वहां मांग होते हुए भी भारत सरकार ने गैर-बासमती चावल की अनुमति नहीं दी, केवल बासमती चावल की अनुमति दी है। इस वजह से देश में चावल के दाम किसानों को नहीं मिल रहे हैं। सरकार ने एमएसपी के माध्यम से 80 रुपए प्रति क्वींटल बढ़ाया था। यह कम बढ़ाया था। सरकार एक तो दाम नहीं देती है और दुनिया में जब हम डब्ल्यूटीओ के सदस्य हैं तो हमें आयात ही क्यों, निर्यात भी करना चाहिए, क्योंकि देश में कृषि उपज में वृद्धि हो रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि चावल के निर्यात पर से निर्बंध हटाया जाए और गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति भी सरकार प्रदान करे। धन्यवाद।